मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

आपका नए भारत में स्वागत है

हरियाणवी राजनीति 3
मोदी का विकल्प ? 4
मॉब लिंचिंग की राजनीति 5
आयुष्मान का बीके अस्पताल 8

वर्ष 31 अंक -36 फ़रीदाबाद 02-08 सितम्बर 2018 फोन : - 9999595632 ₹2.50

दाऊद इब्राहिम की जगह पकड़ा सुधा भारद्वाज को

फरीदाबाद (म.मो.) बीते 28 अगस्त को सुधा भारद्वाज, गौतम नौलखा, अरुण फरेरा, वरवर राव एवं वरनोन गोंजल्विस जैसे मशहूर सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रोफेसर एवं वकीलों को राजनैतिक इशारे पर महाराष्ट्र पुलिस ने अर्बन नक्सल का नाम दे कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का आरोप है कि इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रची है।

1 जनवरी 2018 को भीमकोरेगाँव का 200 वाँ शौर्य दिवस मानाने के लिए इकठ्ठा हुए दलित समुदाय पर दक्षिणपंथी संगठनों ने हमला किया, इसमें एक व्यक्ति की जान भी गई। इस मामले में हुई गिरफ्तारियों में पुलिस के अनुसार एक व्यक्ति की ईमेल खुली मिली जिसमें आगे पूछताछ पर इन सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम सामने आये। वो ईमेल प्रधानमंत्री मोदी को राजीव गाँधी की तरह मारने की साजिश से जुड़ी बतायी गई।

मंगलवार को गिरफ्तार किये गए पांचो मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को बुधवार सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत भी मिल गई जिसमे अब उनके घरों में ही उन्हें नजरबंद कर रखा जाएगा। अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी।

प्रधानमंत्री मोदी को झूठ की कुंजी घुमाने की कुछ ऐसी लत पड़ गयी है कि अब देश भर की पुलिस सरेआम लोकतंत्र और संविधान का गला घोटने पर उतारू है।

इससे पहले भी जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बुद्धिजीवियों के विरूद्ध दर्ज किये मुदकमों से भी भाजपा के चरित्र को देखा जा चुका है। इन पांच सामाजिक कार्यकर्ताओं जिनमें एक की उम्र 80 वर्ष है, से 56 इंच वाले मोदी की जान को खतरा है। इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए एक गुमनाम चिट्ठी का सहारा लिया गया है। ये चिट्ठी पुलिस को भीमाकोरेगांव की हिंसा के एक आरोपी की ईमेल खुली रह जाने से प्राप्त हुई।

दम है तेरे जुल्म में कितना, देख लिया और देखेंगे

जो कहानी पुलिस बता रही है वो किसी हिंदी सिनेमा की पिटी हुई फिल्मी कहानी से भी गई गुजरी जान पड़ती है। भाजपा से जुड़े संगठनों के अनपढ़ आतंकवादी कोड का इस्तेमाल करते हैं और ये पढ़े लिखे कानून के ज्ञाता समाज सेवी प्रधानमंत्री को मारने की चिट्ठी लिख कर मेल भी करेंगे और मेल को खोल कर भी बैठेंगे ताकि पुलिस आये और पकड़ ले।

ध्यान रहे कि पुलिस के अनुसार, भीमकोरेगाँव की हिंसा के विरोध में और मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सुधा भारद्वाज और अन्य कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पुणे में एक सम्मलेन किया। पुलिस के अनुसार इसी सम्मलेन में प्रधानमंत्री को मारने की साजिश रची गई। ऐसा पहली बार सुना जा रहा है कि किसी के कत्ल की मीटिंग खुलेआम हो रही है वो भी देश के प्रधानमंत्री की।

पुलिस की कहानी पर यकीन करने का भरसक प्रयास भी करें तब भी निराशा ही हाथ लगती है। कोरगांव की हिंसा जनवरी माह में होती है जिसमे गिरफ्तार व्यक्ति की ईमेल पुलिस अनुसार यदि मिल गई थी और जून के महीने में अपराधियों ने सुधा एवं अन्य का नाम बताया था तो अब तक पुलिस ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ? क्यों पुलिस ने इतनी 'खूंखार' जिसमे एक 80 साल के वृद्ध भी शामिल हैं को खुला घूमने दिया जिससे मोदी जी की जान का खतरा बना रहे ? अब जब 9 महीने बीत गए और आरबीआई ने नोटबंदी के जिन को बोतल से बाहर निकाल सबको बता दिया कि 99.30 प्रतिशत नोट वापस जमा हो गए तो यकायक मोदी जी की जान को खतरा हो गया ?

भीमाकोरेगाँव शौर्य दिवस का विरोध करते हुए हिन्दू एकता अघाड़ी के मिलिंद एकबोते एवं शिवराज प्रतिष्ठान के संभाजी भिड़े ने दलितों पर आक्रामक हमले किये। इनके खिलाफ भी हिंसा करने और भड़काने का केस दर्ज हुआ पर इसमें से हिंसा के मुख्य आरोपी मिलिंद को जमानत पर छोड़ दिया गया जबकी संभाजी भिड़े को कभी गिरफ्तार ही नहीं किया गया। राजनैतिक हल्कों की माने तो संभाजी भिड़े मोदी के करीबी हैं। इसलिए ये मान लेना चाहिए कि अच्छे दिनों में हत्या करना गौरवशाली कार्य है जबकि कलम चलाना देशद्रोह।

जिन सामाजिक कार्यकर्ताओं को अर्नब गोस्वामी सरीखे बिकाऊ टीवी एंकर ने टुकड़े टुकड़े गैंग का बताया था और आज उन्हें नक्सली बता जेल भेजनी की तैयारी है, उनकी पृष्ठभूमि का सार जानना आवश्यक है। यूएसए

शेष पेज दो पर

पुलिस द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी के विरोध में प्रदर्शन

फ़रीदाबाद 30 अगस्त 2018 देशभर में अलग-अलग शहरों से की जा रही पुलिस द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी के विरोध में बीके चौक फ़रीदाबाद पर जोरदार प्रदर्शन व सभा का आयोजन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पुणे पुलिस द्वारा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी केन्द्र सरकार के इशारे पर की जा रही है।

वक्ताओं ने कहा कि केन्द्र सरकार देशी-विदेशी पूंजीपतियों के लाभ कमाने की खातिर देश में मज़दूर, किसान, आदिवासी, दलित विरोधी नितियों को धड़ल्ले से लागू कर रहीं है। जिससे सभी मेहनतकश शोषित वंचित तबाह बर्बाद हो रहे हैं। दूसरी ओर सरकार उक्त नितियों से असहमत ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, वकीलों, पत्रकारों, लेखकों तर्कवादियों, समाजिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर हमलावर है।

वक्ताओं ने बताया कि सरकार के मंत्री हत्या तथा बलात्कार के दोषियों का बचाव तथा पुरस्कृत कर रहे हैं वहीं सरकार जनता के अधिकारों की रक्षा के लिये काम करने वाले कार्यकर्ताओं को जेल भेज कर इनकी आवाज़ बंद कर रही है। सरकार के इशारे पर की जा रही कार्यवाई लोकतंत्र की हत्या करने के समान है।

सभी वक्ताओं ने सरकार की लोकतंत्र विरोधी कार्रवाई की एक स्वर में निंदा की तथा मांग किया कि मज़दूरों, किसानों, आदिवासियों तथा सोशित वंचितों के अधिकारों की रक्षा के लिये काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को बिना शर्त तत्काल रिहा किया जाए। तथा ऐसे कार्यकर्ताओं को फास्सिट ताकतों से सुरक्षा मुहैया कराई जाए। प्रदर्शन में निम्नलिखित संगठनों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भागीदारी की।

और कितना हँसाओगे नरेंद्र मोदी!

एसपीजी के इतिहास में किसी प्रधानमन्त्री की हत्या की साजिश का पहला मामला! यह सेहरा भी नरेंद्र मोदी के सर ही बंधना था।

श्रीमती इंदिरा गांधी की बतौर प्रधानमन्त्री हत्या हुयी थी लेकिन तब एसपीजी नहीं होती थी। राजीव गाँधी की हत्या हुयी, तब वे भूतपूर्व प्रधानमन्त्री थे और उनकी सुरक्षा में एसपीजी नहीं होती थी।

नरेंद्र मोदी के नाम तमाम तरह के रिकॉर्ड हैं, अब यह भी जुड़ गया कि बतौर प्रधानमन्त्री उनकी हत्या की साजिश का मुकदमा दर्ज हो गया।

साठ से अस्सी के दशक में इन साजिश करने वालों की उम्र चल रही है। सभी अपने-अपने घर पर बैठे इंतजार कर रहे थे कि पुलिस आये महाराष्ट्र से और उन्हें पकड़ ले। दरअसल जून से ही उनका इन्तजार चल रहा था जब अन्य 'साजिशकर्ताओं' ने उनका नाम बताया था पुलिस को।

कहीं आपको हंसी तो नहीं आ रही यह सब पढ़ कर। क्या हमारी पुलिस ऐसे ही फर्जी मामले बनाती है और वह भी प्रधानमन्त्री का नाम लेकर।

नहीं, पुलिस कैसी भी गयी गुजरी हो ऐसी हास्यास्पद कहानी नहीं बनायेगी। हुआ यह कि मोदी का एनएसए अजित डोभाल सारी जिन्दगी आईबी में रहा और रिपोर्ट बनाने का तो मास्टर है पर केस बनाने में जीरो। तो केस तो ऐसा ही बनना था।

हुआ यह भी कि सीबीआई ने कलबुर्गी और गौरी लंकेश की हत्या की जांच में हिन्दू संगठन के बहुत से राज खोल दिए और महाराष्ट्र पुलिस को उनके लोगों की गिरफ्तारी करनी पड़ी। हिंदुत्व पर यह चोट और वह भी अपनी पुलिस के हाथों, कहाँ बर्दाश्त होनी थी। तो उसी पुलिस से अब वामपंथी कार्यकर्ताओं को लपेटे में लेने को कहा गया। यानी संतुलन बैठाने में असंतुलित हो गयी पुलिस की कार्यवाही।

सोचिये, दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। देश के प्रधानमन्त्री की हत्या की साजिश का मुकदमा और देश की सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार साजिशकर्ताओं को ले जाने पर रोक लगा दी। और कितना हंसाओगे नरेंद्र मोदी!

200 बसों का कबाड़ा करने के बाद पुन: सिटी बस सेवा की योजना

फ़रीदाबाद (म.मो.) सुधी पाठक भूले नहीं होंगे कि करीब छ: वर्ष पूर्व जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन (जेएनयूआरएम) के तहत इस शहर को 200 बसें केन्द्र सरकार ने खरीद कर दी थी। दो वर्ष तक तो ये बसें इस इंतज़ार में खड़ी रहीं कि इन्हें नगर निगम चलायेगा या हरियाणा रोडवेज़। अन्त में जब यह काम हरियाणा रोडवेज़ को सौंपा गया तो उनके पास ड्राइवर ही नहीं थे। इधर-उधर से पकड़ कर जब कुछ ड्राइवरों से इन्हें चलवाने का प्रयास किया गया तो वे विफ़ल रहे। ड्राइवरों का कहना था कि इस तरह की असाधारण बस उन्होंने पहले कभी नहीं देखी हैं, चलाना तो दुर की बात। इसलिये 20 ड्राइवरों को स्पेशल ट्रेनिंग के लिये बेंगलुरु भेजा गया।

ट्रेनिंग से लौटे ड्राइवरों ने जब इन बसों को चलाना शुरू किया तो तब तक अधिकांश बसें खड़ी-खड़ी ही खराब हो चुकी थीं। वारंटी समय निकल चुकने की वजह से कम्पनी ने बसों की मुरम्मत करने से इन्कार कर दिया। जैसे-तैसे अनाप-शनाप खर्चे करके इन बसों को चलाया गया। कुप्रबंधन के चलते ये बसें कामयाब नहीं हुई और भारी घाटा देकर लगभग सभी बसें कबाड़ा बन चुकी हैं। अब नये सिरे से स्मार्ट सिटी लिमिटेड प्राइवेट पार्टनर के साथ मिलकर पुन: सिटी बस सेवा शुरू करने की बात कर रही है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड केवल नगर निगम का बदला हुआ नाम है। जो अधिकारी कर्मचारी नगर निगम में रहते हुये निकम्मे-नालायक व भ्रष्टाचारी साबित हो चुके हों तो क्या वे नये नाम (स्मार्ट सिटी लिमिटेड) के नाम से कोई बेहतर काम कर सकेंगे ?

इसमें कोई दो राय नहीं कि 20 लाख की आबादी वाले इस शहर में एक कोने से दूसरे कोने तक आने-जाने के लिये सिटी बस सेवा की सख्त जरूरत है। इसके लिये वर्ष 2019 में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के नाम से नगर निगम ने 90 बसें खरीदने की योजना बनायी है जिसे मंजूरी के लिये हरियाणा सरकार को भेज दिया गया है। समझने वाली बात यह है कि जो नगर निगम अपनी नियमित आमदनी के अतिरिक्त 400 करोड़ स्मार्ट सिटी के नाम से भी डकार चुका हो और उसके बावजूद शहर में कहीं स्मार्टनेस नज़र न आती हो तो वह सिटी बस सेवा क्या दे पायेगा ?

सैंकड़ों की संख्या में सीवर लाइन के खुले मैन होलों को देखा जा सकता है इनमें गिर कर मरना अथवा घायल होना एक आम बात हो गयी है। आवारा पशुओं पर निगम का कोई नियंत्रण नहीं है। साडों की टक्कड़ से अनेकों लोग घायल होते रहते हैं। कुत्ता काटे के शिकारों की संख्या प्रति वर्ष 30 हज़ार को पार कर चुकी हैं। चार बुंद पानी बरसते ही शहर किचर से इस कदर भर जाता है कि पैदल चलना दूभर हो जाये। ऐसे नगर निगम को स्मार्ट सिटी लिमिटेड का नाम देने से भला बसें कैसे चल पायेंगी ?

परिवहन सेवा अपने आप में एक विशेष दक्षतापूर्ण व्यवसाय है। जनता के पैसे से केवल बसें खरीद लेने मात्र से यह सेवा दे पाना सम्भव नहीं हो सकता। इसका अनुभव छ: वर्ष पूर्व किया जा चुका है। हरियाणा रोडवेज वर्षों पुराना एक सरकारी उपक्रम है। प्राइवेट बसों के मुनाफ़े को देखते हुये 70 का दशक प्रारम्भ होते-होते तत्कालीन मुख्यमंत्री बंशीलाल ने राज्य की तमाम प्राइवेट बसों के परमिट रद्द करके तमाम मार्गों पर

शेष पेज दो पर